OFFICE OF SHRI SHAKTISINHJI GOHIL

NATIONAL SPOKEPERSON, ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE

http://www.shaktisinhgohil.com

Press Note — 20th March, 2014

- किसी राजनीति के लिए नहीं परंतु राष्ट्रीय सुरक्षा में गंभीर अनियमितताओं की वजह से राष्ट्र के हित में यह स्पष्टता करनी पडी है ।
- राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अत्यंत गंभीर स्थिति के बारे में गुजरात के मुज़्यमंत्री का ध्यान खींचने के बावजूद कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलने पर राष्ट्रीय हित में पत्रकार परिषद आयोजित करनी पडी ।
- पाकिस्तान से नजदीक गुजरात के दरियाई तट पर सुरक्षा की लापरवाही ।
- केन्द्र सरकारने अत्याधुनिक ३० बोट्स नाईट विझन कैमरे के साथ गुजरात को दी, फिर भी गुजरात के दरियाई तट पर नाईट पेट्रोलिंग नहीं हो रहा ।
- दरियाई तट पर बनाये जानेवाले कोस्टल पोलीस स्टेशन अमदावाद और बनासकांठा में बनाये गये ।
- गुजरात में २१ कोस्टल चेक पोस्ट में से एक भी कार्यरत नहीं ।
- पाकिस्तान से नजदीक कच्छ के २३८ कि.मी. के दरियाई तट पर एकमात्र पोलीस स्टेशन ।
- हर्षद माता मंदिर से द्वारका तक के दरियाई तट के कोस्टल पोलीस स्टेशन की जगह बदल कर गुजरात सरकारने आतंकवादीओं के लिए खुला छोडा ।
- केन्द्र सरकारने पेट्रोलिंग बोट को वार्षिक १८०० घंटे दरियाई पेट्रोलिंग की सूचना दी होने के बावजूद गुजरात में ७८% से ९१% कम पेट्रोलिंग ।
- दरियाई पेट्रोलिंग की बोट्स महिनों से जमीन पर ।
- देश की सुरक्षा के लिए ओलवेधर जेट्टी गुजरात के दरियाई तट पर बनानी थी, लेकिन गुजरात सरकारने एक भी नहीं बनाई ।
- ए.टी.एस. में खाली जगह भरने के २००९ के केग के रिपोर्ट में निर्देश होने के बावजूद गुजरात में आज भी ८% से १००% जितनी जगह ऐन्टी टेररीस्ट स्कवोड में खाली ।
- मरीन एक्स्लुझीव ईन्टेलिजन्स एण्ड ईन्वेस्टीगेशन वींग गुजरात में स्थापित करनी थी, लेकिन गुजरात में स्थापित न हुई ।
- मुंबई हमले में भी आतंकवादी गुजरात के पोरबंदर की बोट ले गये थे ।
- गुजरात के मुज़्यमंत्री देश को बतायें कि केग की टिप्पणी होने पर भी सुरक्षा की अनदेखी क्युँ कि गई ?
- आतंकवाद के खिलाफ कडी सुरक्षा व्यवस्था क्यो नहीं ?

काँग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्तिसिंह गोहिलने बताया है कि, राष्ट्र की सुरक्षा को काँग्रेस पक्षने हमेशा राजनीति से परे रखा है । राष्ट्रीय सुरक्षा की अतिगंभीर खामियाँ प्रेस और मीडीया के सामने सार्वजनिक करनी पड रही है । राष्ट्रीय सुरक्षा की अतिगंभीर अनियमितता गुजरात के मुज़्यमंत्री के ध्यान पर लाकर वह बात अत्यंत गोपनीय रखी गई थी । गुजरात के मुज़्यमंत्री की ओर से समय सीमा में प्रत्युत्तर नहीं मिलने के बाद एक हज़्ते बाद राष्ट्रीय हित में गुजरात की दरियाई तट पर सुरक्षा व्यवस्था में अनियमितता के बारे में प्रेस और मीडीया का ध्यान आकर्षित करना पड रहा है ।

पाकिस्तान की सरहद से नजदीकवाला राज्य गुजरात राज्य है । गुजरात का १,६४० कि.मी. लंबा दरियाई तट गुजरात के १३ जिलों को छूता है । सबसे लंबे दरियाई तटवाले गुजरात राज्य के नजदीक पाकिस्तान की सरहद है । इस कारणवश राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और आतंकवादी एवं गुन्हाहित प्रवृत्तियाँ रोकने के लिए गहन दरियाई सुरक्षा गुजरात के दरियाई तट पर अत्यंत आवश्यक है । ० से १२ नोटीकल माईल तक के दरियाई तट की सुरक्षा की जिज़्मेवारी राज्य के पुलीस दल की होती है । वर्ष २००८ में हुए मुंबई हमले में शामिल आतंकवादी गुजरात राज्य के पोरबंदर की कुबेर बोट लेकर आये थे । दरियाई तट की सुरक्षा के लिए भारत सरकारने अत्यंत गंभीरतापूर्ण रूप से कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम (दरियाई सुरक्षा योजना, CSS) २००५ में बनाकर भारत सरकार के गृह मंत्रालयने गुजरात राज्य को करोडों रूपये की सहायता दी है । परंतु गुजरात सरकारने दरियाई सुरक्षा की अनदेखी कर दरियाई सुरक्षा योजना के कामों को पूर्ण करने के बजाय जवाबदारी से दूर रह पूर्ण रूप से दरियाई तट खुला छोड दिया है ।

कोंग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्तिसिंह गोहिलने देश की सुरक्षा की अत्यंत गंभीर बातों के तहत चिंता व्यक्त कर गुजरात के दरियाई तट की सुरक्षा की लापरवाही गुजरात सरकार द्वारा की जा रही है उसके पुज़्ता सबुत दिये । भारत सरकारने जनवरी, २००६ में गुजरात सरकार को १० कोस्टल पोलीस स्टेशन, २५ कोस्टल चेक पोस्ट, ४६ कोस्टल आउट पोस्ट बनाने के लिए और फर्निचर एवं अन्य जरूरी साधन-सामग्री के लिए बहुत बडी राशि दी थी । इसके अलावा ३० अत्याधुनिक बोट्स भारत सरकारने गुजरात सरकार को दी थी । परंतु गुजरात सरकारने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए दरियाई सुरक्षा की योजना की अमलवारी करनी थी, उसमें संपूर्ण उदासीनता दिखाई । दरियाई तट की सुरक्षा के लिए जिन बोटों को रात्रि पेट्रोलिंग करना था, वह नाईट विझन कैमरे से सुसज्ज बोट्स गुजरात को दी होने के बावजूद गुजरात सरकारने रात्रि पेट्रोलिंग के लिए उन बोट्स का उपयोग नहीं किया ।

जामनगर और कच्छ जिले की सरहद पाकिस्तान से सबसे नजदीक है । यह दरियाई इलाका दरियाई सुरक्षा के लिए अत्यंत संवेदनशील है । इस अत्यंत संवेदनशील दरियाई तट के २३८ कि.मी. की कच्छ की सरहद पर एकमात्र पोलीस स्टेशन बनाया गया है । दरियाई सुरक्षा के प्लान अंतर्गत जितने बनाने चाहिए थे उतने पोलीस स्टेशन बगैर कारण नहीं बनाये गये है । हजीरा एवं पीपावाव से डायवर्ट की हुई बोट द्वारा अत्यंत संवेदनशील दरियाई तट कवर नहीं हो पाता । उसी तरह जामनगर जिले के अत्यंत संवेदनशील दरियाई तट पर दो कोस्टल पोलीस स्टेशन की जगह गुजरात सरकारने पुज़्ता कारण दिये बिना बदल दी है । भाटिया का कोस्टल पोलीस स्टेशन वाडीनार और हर्षद माता मंदिर के पास का

कोस्टल पोलीस स्टेशन ओखा में बदली कर दिया गया है । उसके कारण द्वारिकाधीश मंदिर से लेकर हर्षद माता मंदिर तक का दरियाई तट किसी भी सुरक्षा एवं पेट्रोलिंग बगैर का हो गया है । इन पोलीस स्टेशनों के स्थल बदलने के लिए मूल प्लान में बताये गये पोईन्ट्स को गुजरात सरकारने बदल कर राष्ट्र की सुरक्षा के साथ गंभीर रूप से समझौता किया है ।

कच्छ में माता का मढ, हाजीपीर की जगह, जामनगर जिले में द्वारिकाधीश का मंदिर एवं हर्षद माताजी का मंदिर, वह हिन्दु एवं मुस्लिम धर्म के लोगों का आस्था का बहुत बडा केन्द्र है । इन जगहों पर सुरक्षा का कडा प्रबंध किया जाना चाहिए, उसके बजाय दरियाई सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकारने दिये हुए प्लान और पर्याप्त राशि के बावजूद इन धार्मिक स्थानों की सुरक्षा में बहुत खामियाँ रखी गई है । दरियाई तट पर पोलीस स्टेशन बनाने के लिए केन्द्र सरकारने परियोजना को अनुमोदन दे दिया है और उसके लिए पर्याप्त राशि भी गुजरात को दी जा चूकी है । गुजरात सरकारने दरियाई तट पर बनाये जानेवाले पोलीस स्टेशन अमदावाद और बनासकांठा में बनाकर कोस्टल पोलीस स्टेशन की राशि खर्च कर दी है, वह दिखा रहा है कि गुजरात सरकार राष्ट्र की सुरक्षा के साथ किस प्रकार समझौता कर रही है । गुजरात में २१ कोस्टल चेक पोस्ट तैयार करनी थी, दुर्भाग्य से गुजरात की सभी २१ कोस्टल चेक पोस्ट स्टाफ की कमी के कारण परिचालित नहीं है । जबकि २९ कोस्ट आउट पोस्ट स्टेशनमें से १५ परिचालित नहीं है, क्योंकि गुजरात सरकारने वहाँ कोई स्टाफ नहीं रखा है । जो १४ कोस्टल आउट पोस्ट स्टेशन परिचालित है, उसमें भी सिर्फ २ या ३ पुलिसवालों को नियुक्त किया गया है, जो आसीस्टन्ट सब ईन्स्पेक्टर या हेड कोन्स्टेबल या पोलीस कोन्स्टेबल रेन्क के हैं । इस तरह अनुमोदित स्थापना के प्रतिशत में केवल २९% पोलीस स्टाफ को भर्ती किया गया है ।

गुजरात के दरियाई तट पर सभी मौसमों में इस्तेमाल की जा सके ऐसी जेट्टीयाँ बनानी थी, कि जिनसे गुजरात के दरियाई तट की पूरी सुरक्षा हो और २४ घंटे पेट्रोलिंग हो सके । गुजरात सरकार की आपराधिक लापरवाही के कारण गुजरात के दरियाई तट पर सुरक्षा के लिए सभी मौसमों में इस्तेमाल की जा सके ऐसी एक भी जेट्टी बनाई गई नहीं है । गुजरात मेरीटाइम बोर्ड एवं अन्य निजी जेट्टीओं के उपयोग के कारण सुरक्षा के लिए इन्टरसेप्ट बोट्स का व्यावहारिक उपयोग नहीं किया जा सकता है । स्वतंत्र अलग जेट्टी नहीं होने के कारण निजी कंपनियाँ और मछली पकडनें की नावों के साथ दरियाई सुरक्षा का पेट्रोलिंग होने से सभी को मालुम हो जाये उस तरह का पेट्रोलिंग होता है । कई बंदरगाहों पर अन्य विपरीत कारणों के अंतर्गत सुरक्षा के लिए नाँव उपयोग में नहीं ली जा सकती है । केग के रिपोर्ट की कोपी दिखाकर श्री गोहिलने यह प्रस्थापित किया है कि, गुजरात सरकार को सुरक्षा के लिए दी गई नाँव का उपयोग नहीं हो रहा है ।

कोस्टल सिक्योरीटी प्लान के अंतर्गत गुजरात के अत्यंत संवेदनशील दरियाई तट की सुरक्षा को ध्यान में रखकर केन्द्र सरकारने मरीन ऐक्स्लुझीव ईन्टेलिजन्स एण्ड ईन्वेस्टीगेशन वींग की स्थापना हेतु पर्याप्त राशि और निर्देश गुजरात सरकार को दिये है । इस वींग द्वारा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निष्पादन दरियाई ईलाकों में हो रही शंकास्पद प्रवृत्तियाँ, दरियाई तट पर व्यक्तियों का आवागमन, दरियाई इलाकों में

आवागमन करते लोग कौन है और किस कारण मिल रहे है, उसकी जानकारी इकठ्ठा करने की थी, परंतु गुजरात सरकारने मरीन ऐक्स्लुझीव ईन्टेलिजन्स एण्ड ईन्वेस्टीगेशन वींग की स्थापना ही नहीं की है ।

भारत सरकारने ३० अत्याधुनिक इन्टरसेप्टर बोट्स गुजरात को दी है, जिसमें एक अत्याधुनिक २ टन की और एक ५ टन की शक्तिशाली बोट है । सितम्बर २००९ और अक्तुबर २०१० में गुजरात सरकार को यह बोट्स देकर भारत सरकारने निर्देश दिये थे कि, इन बोट्स द्वारा गुजरात के दरियाई तट की सुरक्षा हेतु हर बोट को मासिक १५० घंटे और वार्षिक १८०० घंटे दरियाई पेट्रोलिंग करना होगा । भारत सरकार के यह निर्देश के बावजूद गुजरात सरकारने दरियाई तट की सुरक्षा के प्रति लापरवाही दिखाकर पेट्रोलिंग ७८% से लेकर ९१% तक कम किया है । राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्तिसिंह गोहिलने गुजरात में जिन बोट्स का पेट्रोलिंग कम हुआ है, उसका पूरा विवरण प्रेस और मीडीया को दिया है । श्री गोहिलने कई बोट्स जिनको पानी से निकालकर बाहर जमीन रख दिया गया है, उनके फोटोग्राफ्स भी दिये है ।

२००९ में केग के रिपोर्ट में गुजरात सरकार की सुरक्षा के लिए घोर लापरवाही की सज़्त शब्दों में आलोचना की गई थी । केग के इस रिपोर्ट की नकल श्री गोहिलने प्रेस और मीडीया को देकर बताया है कि, २००९ में केग के रिपोर्ट के पेज नं. १३, पेरा नं. १, ११, ४ में टिप्पणी की गई थी कि, गुजरात में ऐन्टी टेररीस्ट स्कवोड की रचना १९९३ में हुई थी, परंतु वर्तमान समय में विभिन्न संवर्ग में ८% से लेकर १००% जितनी जगह खाली है और उसमें भी उच्चाधिकारीयों की जगह सबसे ज्यादा खाली है । इन खाली जगहों की वजह से आज ए.टी.एस. कागज पर ही मौजूद है । इन टिप्पणीयों के बाद गुजरात सरकारने ए.टी.एस. में सुधार करने के बजाय वर्तमान समय में गुजरात ए.टी.एस. में २००९ में जो जगह खाली थी, उससे भी ज्यादा पोलीस जवान और उच्चाधिकारीयों की जगह खाली कर दी है । वर्तमान समय में डी.आई.जी. कक्षा की १००% जगह खाली है । सुप्रिन्टेन्डन्ट ओफ पोलीस कक्षा की १००% जगह खाली है । डी.वाय.एस.पी. कक्षा की ६७% जगह खाली है और उसी तरह पोलीस इन्स्पेक्टर, पोलीस सब इन्स्पेक्टर, हेड कोन्स्टेबल और कई जगहों पर संवर्ग अनुसार जगह खाली है । केग की टिप्पणीयों के बावजूद गुजरात सरकार सुरक्षा के प्रति लापरवाही रख रही है, इससे मालुम होता है कि सरकार के इरादे नेक नहीं लग रहे हैं ।

२००९ में केग के रिपोर्ट में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि, पेट्रोलिंग करते वाहनों में ग्लोबल पोझीशनींग सिस्टम और ओटोमेटीक व्हीकल लोकेटर सिस्टम प्रस्थापित होनी चाहिए । उसके लिए पर्याप्त राशि भी उपलब्ध होने के बावजूद गुजरात सरकारने उसको कार्यान्वित नहीं किया है और इस तरह गुजरात में सुरक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है । गुजरात में बंदूके है परंतु उसके कार्ट्रेज नहीं है, और कुछ मामलों में तो यह १००% दोषयुक्त होने के आंकडे केग द्वारा दिये जा चूके है । गुजरात सरकारने इसको खरीद करने के समय पर ऑर्डर नहीं दिये जाने की भी आलोचना केग के रिपोर्ट में की गई है ।

उपर बताई चीजें राष्ट्र की सुरक्षा के लिए एक चिंता का विषय है । भारतीय जनता पक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा का वोटबेंक के लिए उपयोग करता है और गुजरात के मुज़्यमंत्री तो चुनाव के समय गैर जिम्मेदार

मुद्दों को उपस्थित कर, देश के वडाप्रधान को पत्र लिखकर, उस पत्र को मीडीया में प्रस्तुत कर, राष्ट्रीय सुरक्षा की किमत पर वोटबेंक की राजनीति करते है, ऐसे कई मौजूदा उदाहरण हैं । कोंग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्तिसिंह गोहिलने बताया है कि, राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मुद्दों पर उन्होंने दि. ३ मार्च, २०१४ को गुजरात के मुज़्यमंत्री को पत्र लिखा था और यह पत्र किसी जगह सार्वजनिक न हो जाये उसकी सावधानी रखी थी । उन्होंने लिखे इस पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के इन सभी मुद्दों पर चिंता व्यक्त कर गुजरात के मुज़्यमंत्री को स्पष्टतापूर्वक जवाब देने के लिए १० दिन का समय भी दिया था । उनके इस पत्र का समय सीमा में गुजरात के मुज़्यमंत्री की ओर से किसी भी तरह का प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में यह मुद्दें पेश करने के लिए मजबुर हुए हैं ।

गुजरात के मुज़्यमंत्री देश की जनता को बतायें कि केग की टिप्पणी होने के बावजूद भी सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर अनियमितता दूर क्यों नहीं की गई ? शक्तिसिंह गोहिल द्वारा लिखित अत्यंत गोपनीय पत्र का उत्तर क्यों नहीं दिया गया ? आतंकवाद के खिलाफ कडी सुरक्षा व्यवस्था रखने के बजाय गुजरात की सरहद आतंकवादीओं के लिए खुली क्यों छोड दी गई है ? अपनी चारों ओर मजबूत सुरक्षा व्यवस्था रखना और घर के सामने अक्षरधाम मंदिर को आतंकवादीओं के हवाले करने का इतिहास भी गुजरात के इसी मुज़्यमंत्री का रहा है । इस संदर्भ में राष्ट्रीय हित में गुजरात में राष्ट्रीय सुरक्षा की जो गंभीर और चिंताजनक स्थिति है उसको देश समक्ष रखने को मजबूर हुआ हूँ ऐसा श्री शक्तिसिंह गोहिलने बताया है ।

सूचना :- इस प्रेसनोट से संबंधित डॉक्युमेण्ट्स की कॉपी पढने और पाने के लिए http://www.shaktisinhgohil.com पर क्लिक करें ।

प्रति,

संपादक,

यह प्रेसनोट आपके प्रतिष्ठित अखबार में प्रदर्शित करने के लिए मान. शक्तिसिंहजी गोहिलने बिनती की है ।

(सुनिल रामी)

निजी सहायक